सत्यमेव जयते
Government of India
NCGG
National Centre for Good Governance
The Torch Bearer of Good Governance

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

सत्यमेव जयते
Government of India
NCGG
National Centre for Good Governance
The Torch Bearer of Good Governance

वार्षिक रिपोर्ट
2024-25

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

अंतर्वस्तु	पृष्ठ संख्या
कार्यकारी सारांश	1
प्रस्तावना	2 - 4
केंद्र के बारे में	2
लक्ष्य और उद्देश्य	2 - 3
राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) का अधिदेश	3
शासी निकाय	3
प्रबंधन समिति	4
वर्ष 2024–25 के दौरान एनसीजीजी की गतिविधियाँ	4 - 25
अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम	4 - 10
जिला जुड़ाव तथा अध्ययन दौरे और ताजमहल का दौरा	10 - 11
क्षमता विकास कार्यक्रमों और जिला जुड़ाव में एनसीजीजी द्वारा शुरू किए गए नवाचार	12 - 13
घरेलू क्षमता विकास कार्यक्रम	13 - 14
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलईएडीएस)	14 - 15
इंटर्नशिप कार्यक्रम	15 - 16
वेबिनार श्रृंखला	16 - 19
प्रकाशन	19 - 20
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग	20 - 21
आउटरीच की गतिविधियाँ	21 - 23
प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी	24
वित्त	24 - 25
अनुलग्नक	26 - 34
अनुलग्नक-I: एनसीजीजी का शासी निकाय	26
अनुलग्नक-II: एनसीजीजी की प्रबंधन समिति	27
अनुलग्नक-III: 2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम - एकल देशीय	28
अनुलग्नक-IV: 2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम - बहु-देशीय	29
अनुलग्नक-V: 2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा संचालित घरेलू क्षमता विकास कार्यक्रम	30
अनुलग्नक-VI: 2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आयोजित एनसीजीजी - आईएनएसए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलईएडीएस)	30
अनुलग्नक-VII: एनसीजीजी के इंटर्नशिप कार्यक्रम का विवरण	30
अनुलग्नक-VIII: 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता के लिए चयनित पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला	31
अनुलग्नक-IX: 2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा आयोजित सुशासन: नीतियां और अभ्यास वेबिनार श्रृंखला	32
अनुलग्नक-X: 2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन	33
अनुलग्नक-XI: 2024-25 के दौरान राष्ट्रीय संस्थानों/विभागों/विश्वविद्यालयों के साथ एनसीजीजी द्वारा हस्ताक्षरित घरेलू समझौता ज्ञापन	34

कार्यकारी सारांश

यह वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) की गतिविधियों और उपलब्धियों पर प्रकाश डालती है, जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत 2014 में स्थापित एक शीर्ष स्तरीय स्वायत्त संस्थान है। यह रिपोर्ट 1 अप्रैल, 2024 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि कवर करती है और भारत और अन्य विकासशील देशों में शासन, नीतिगत सुधारों, क्षमता विकास और सिविल सेवकों और टेक्नोक्रेट के प्रशिक्षण के लिए एनसीजीजी की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

अपनी स्थापना के बाद से एनसीजीजी ने अपने कार्यक्रमों का काफी विस्तार किया है, जो शुरू में 5 कार्यक्रमों के साथ एक देश की सेवा करने से लेकर वित्त वर्ष 2024-25 में 28 कार्यक्रमों के साथ 47 देशों को जोड़ने तक विकसित हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, एनसीजीजी ने मालदीव, श्रीलंका, कंबोडिया, मेडागास्कर, मॉरीशस और मलेशिया सहित कई देशों के साथ प्रभावशाली सहयोग किया है। उल्लेखनीय उपलब्धियों में समझौता ज्ञापनों द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण के लक्ष्यों के अनुसार 72 से अधिक कार्यक्रमों के माध्यम से बांग्लादेश के 2,658 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना तथा 27 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से मालदीव के 1,110 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देना शामिल है।

घरेलू स्तर पर, एनसीजीजी ने राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार जैसी पहलों के साथ अपनी उत्कृष्टता जारी रखी है, जिसमें 21,000 से अधिक प्रतिभागी शामिल हुए। आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थानों और अन्य संगठनों/स्वायत्त निकायों के सहयोग से एनसीजीजी अपने स्वयं के वेबिनार भी आयोजित करता है।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) जैसे राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख भारतीय संस्थानों के साथ साझेदारी का उद्देश्य घरेलू क्षमता विकास कार्यक्रमों का स्तर बढ़ाना और एनसीजीजी के अनुसंधान पहलू को बढ़ाना है। आईआईएम विशाखापत्तनम के साथ एक घरेलू क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

2024-25 में एनसीजीजी-आईएनएसए एलईएडीएस पहल के तहत, सरकारी प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के दो बैचों का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, एनसीजीजी ने 2024-25 में एक इंटर्नशिप कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया।

राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षमता विकास के प्रति एनसीजीजी का व्यापक दृष्टिकोण प्रभावी शासन और लोक प्रशासन में सुधार के लिए उत्प्रेरक के रूप में इसकी भूमिका को रेखांकित करता है और जो सीमाओं के पार भी सतत् विकास और संस्थागत सुदृढ़ीकरण में योगदान देता है। यह रिपोर्ट शासन में सुधार लाने और घरेलू और सार्वजनिक सेवा सुपुर्दगी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए एनसीजीजी के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

प्रस्तावना

I. केंद्र के बारे में

भारत सरकार द्वारा 2014 में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) की स्थापना की गई। केंद्र की उत्पत्ति राष्ट्रीय प्रशासनिक अनुसंधान संस्थान (एनआईएआर) से हुई है, जिसकी स्थापना 1995 में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) द्वारा की गई थी। शुरू में, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) इसके संचालन की देखरेख के लिए जिम्मेदार था। हालांकि 8 नवंबर, 2017 से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) एनसीजीजी का प्रशासनिक विभाग रहा है।

एनसीजीजी सभी क्षेत्रों में स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक नीति और शासन संबंधी मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला का समाधान करता है। केंद्र को सुशासन, नीतिगत सुधार, भारत तथा अन्य विकासशील देशों के सिविल सेवकों और टेक्नोक्रेटों के क्षमता विकास और प्रशिक्षण के क्षेत्रों में कार्य करने का अधिदेश दिया गया है। इसके अतिरिक्त, यह विभिन्न पहलों और सर्वोत्तम प्रथाओं पर सूचना का राष्ट्रीय भंडार उपलब्ध कराने वाले थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, जो सुशासन, पारदर्शिता और बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण को बढ़ावा देती हैं।

II. लक्ष्य और उद्देश्य

एनसीजीजी की स्थापना करते समय निम्नलिखित लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं:

1. प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय क्षेत्रों में शासन और नीतिगत सुधारों के लिए थिंक टैंक बनना;
2. सरकार और उसके अर्ध-सरकारी संगठनों के भीतर सुशासन, ई-गवर्नेंस, नवाचार और परिवर्तन प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं, पहलों और कार्यप्रणालियों पर सूचना के राष्ट्रीय भंडार के रूप में कार्य करना;
3. राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विनियामक और विकास प्रशासन, लोक नीति, शासन और सार्वजनिक प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर क्रियात्मक अनुसंधान और क्षमता विकास शुरू करना और उसमें भाग लेना;
4. शासन के प्रमुख मुद्दों पर सलाह देना तथा भारत सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच तालमेल विकसित करना;

5. शासन में नवीन विचारों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साझाकरण और अनुकरण को बढ़ावा देना;
6. उपर्युक्त क्षेत्रों में अनुसंधान और क्षमता विकास में लगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, चाहे वे सरकार के भीतर हों या बाहर, के साथ बातचीत करना; और
7. देश के अंदर और बाहर परामर्शी सेवाओं प्रदान करने में शामिल होना।

III. एनसीजीजी का अधिदेश

1. नीतिगत सुधारों और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देना;
2. सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास और प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना और उनका संचालन करना;
3. शासन संबंधी मुद्दों के व्यावहारिक समाधान के लिए व्यापक अनुसंधान और विश्लेषण करना;
4. शासन में सूचना, ज्ञान, विचारों और विशेषज्ञता के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कई विकासशील देशों के साथ सहयोग करना;
5. विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रिपोर्ट, केस स्टडी, मोनोग्राफ और सर्वोत्तम प्रथाएं प्रकाशित करना; और
6. नागरिक केंद्रित शासन के लिए आधुनिक संचार प्रौद्योगिकियों और आउटरीच का उपयोग करना।

IV. शासी निकाय

एनसीजीजी के मामलों का प्रबंधन शासी निकाय के समग्र मार्गदर्शन और निर्देशन के तहत किया जाता है, जिसका नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं। इसमें भारत सरकार के 9 मंत्रालयों/विभागों के सचिव सदस्य के रूप में हैं तथा 5 व्यक्ति अर्थात शिक्षाविद, प्रख्यात प्रशासक, विशेषज्ञ, प्रख्यात नवप्रवर्तक और प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख सदस्य के रूप में हैं। महानिदेशक, जो एनसीजीजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, शासी निकाय के सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करते हैं (अनुलग्नक-I)।

V. प्रबंधन समिति

एनसीजीजी की एक प्रबंधन समिति है, जो वार्षिक योजनाओं, कार्यक्रमों की निगरानी और कार्यान्वयन, सोसायटी के योगदान और निधि आदि के संबंध में सोसायटी के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। डीएआरपीजी के सचिव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हैं; तथा 9 मंत्रालयों/विभागों के सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति, मंत्रिमंडल सचिवालय से समन्वय सचिव; विशेष सचिव/एएस और वित्त सचिव (गृह मंत्रालय) इसके सदस्य के रूप में और महानिदेशक, एनसीजीजी सदस्य सचिव के रूप में हैं (अनुलग्नक-II)।

वर्ष 2024–25 के दौरान एनसीजीजी की गतिविधियाँ

I. अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम

वैश्विक आउटरीच:

एनसीजीजी ने 2024-25 में क्षमता विकास कार्यक्रमों का आयोजन करके अपने वैश्विक फुटप्रिंट का महत्वपूर्ण विस्तार किया, जिनमें 47 देशों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, तथा भारत के गवर्नेंस मॉडल और सर्वोत्तम प्रथाओं को बढ़ावा दिया। विदेश मंत्रालय (आईटीईसी और आईओआर प्रभाग) - एनसीजीजी सहयोग इस वैश्विक पहुंच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मालदीव, श्रीलंका, कंबोडिया, गाम्बिया, तंजानिया, केन्या और बांग्लादेश जैसे देशों के अंतर्राष्ट्रीय सिविल सेवकों के बीच शासन की प्रभावी प्रथाओं का प्रसार किया है। एनसीजीजी ने वर्ष के दौरान अफ्रीकी क्षेत्र के देशों, एफआईपीआईसी/आईओआरए देशों, एलएसी देशों, आसियान/आईओआरए देशों और बिम्सटेक देशों के लिए बहुपक्षीय क्षमता विकास कार्यक्रमों का भी आयोजन किया है, जो इसे वैश्विक स्तर पर क्षमता विकास के लिए अग्रणी संस्थानों में से एक बनाता है।

बांग्लादेश:

विदेश मंत्रालय द्वारा 2013 में एनसीजीजी को बांग्लादेश के 1,500 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने का अधिदेश दिया गया था। 1,500 सिविल सेवकों के सफल प्रशिक्षण के बाद, बांग्लादेश सरकार के लोक प्रशासन मंत्रालय ने अगले छह वर्षों में बांग्लादेश के 1,800 अन्य सिविल सेवकों को प्रशिक्षण देने के लिए 11 फरवरी, 2019 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनसीजीजी ने इस समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश के 2,597 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण को कवर करते हुए 71 बैचों के लिए क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान, बांग्लादेश के 61 सिविल सेवकों के दो बैचों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। एनसीजीजी ने मार्च 2025 तक बांग्लादेश के 2,658 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है (अनुलग्नक-III)।

मालदीव:

8 जून, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक राजकीय यात्रा के दौरान, भारत और मालदीव ने अगले 5 वर्षों में मालदीव के 1,000 सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीबीटीपी) को लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। तदनुसार, एनसीजीजी ने 32 क्षमता विकास

कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन किया, जिसमें उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल के लिए एक कार्यक्रम और भ्रष्टाचार निरोधक आयोग (एसीसी), मालदीव और मालदीव के सूचना आयोग कार्यालय (आईसीओएम) के लिए दो विशेष कार्यक्रम शामिल हैं।

मालदीव के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम पर एनसीजीजी और मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मालदीव के 1000 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 9 अगस्त 2024 की प्रभावी तिथि के साथ 5 वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकृत किया गया।

वर्ष 2024-25 में मालदीव गणराज्य के 104 सिविल सेवकों ने 3 बैचों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है। एनसीजीजी ने मार्च 2025 तक मालदीव के 1110 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है (अनुलग्नक-III)।

श्रीलंका:

एनसीजीजी और श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान, लोक प्रशासन मंत्रालय, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार, श्रीलंका के बीच श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन पर 10 दिसंबर, 2024 को हस्ताक्षर किए गए, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए या भारत में श्रीलंका के 1500 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिए जाने तक प्रभावी रहेगा।

एनसीजीजी ने मार्च, 2024 तक श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। एनसीजीजी ने वर्ष 2024-25 के दौरान श्रीलंका के 200 सिविल सेवकों के लिए दो सप्ताह की अवधि वाले पांच क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए हैं। एनसीजीजी ने मार्च 2025 तक 254 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है, जिसमें श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सचिव के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल और वरिष्ठ स्तर के तेरह सिविल सेवक शामिल हैं (अनुलग्नक III)।

कंबोडिया:

एनसीजीजी कंबोडिया के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर क्षमता विकास कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित करता रहा है और मार्च, 2024 तक कंबोडिया के कुल 156 सिविल सेवकों को कवर करते हुए 4 कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक संचालन कर चुका है। किंगडम ऑफ कंबोडिया के सिविल सेवा मंत्रालय और भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के बीच 22 अप्रैल 2024 को 5 वर्ष की अवधि के लिए सिविल सेवाओं में मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

वर्ष 2024-25 के दौरान, कंबोडिया के 237 सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर दो सप्ताह के 6 क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। एनसीजीजी ने मार्च 2025 तक कंबोडिया के 393 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है (अनुलग्नक-III)।

गाम्बिया:

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग और लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति कार्यालय, गाम्बिया गणराज्य के बीच कार्मिक, प्रशासन और शासन संबंधी सुधारों के नवीनीकरण के संबंध में 18 जून 2024 को 5 वर्ष की अवधि के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जो 8 जुलाई, 2024 (पिछले समझौता ज्ञापन की समाप्ति की तारीख) से प्रभावी हो गया है।

एनसीजीजी ने मार्च, 2024 तक गाम्बिया के सिविल सेवकों के लिए तीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। वर्ष 2024-25 के दौरान, गाम्बिया के 48 सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर दो सप्ताह की अवधि वाले दो क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

एनसीजीजी ने मार्च 2025 तक 138 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें गाम्बिया के स्थायी सचिव भी शामिल हैं (अनुलग्नक-III)।

तंजानिया:

वर्ष 2024-25 के दौरान, एनसीजीजी ने 6 मई, 2024 से 17 मई, 2024 के दौरान तंजानिया के सिविल सेवकों के लिए लोक निर्माण हेतु परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर दो सप्ताह का क्षमता विकास कार्यक्रम (सीबीपी) आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सड़क एजेंसी, ऊर्जा मंत्रालय, योजना आयोग, तंजानिया बिल्डिंग एजेंसी, तंजानिया रेलवे कॉर्पोरेशन, आवास निवेश, रैपिड ट्रांजिट एजेंसी, ई-गवर्नमेंट प्राधिकरण, ऊर्जा और जल नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रपति कार्यालय लोक सेवा प्रबंधन और सुशासन, क्षेत्रीय प्रशासन और स्थानीय सरकार, पशुधन और मत्स्य पालन आदि जैसे तंजानिया के विभिन्न संगठनों और मंत्रालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 39 अधिकारियों ने भाग लिया (अनुलग्नक-III)।

केन्या:

केन्या गणराज्य के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए 13 से 18 जनवरी 2019 तक नेतृत्व और राष्ट्रीय परिवर्तन पर एक सप्ताह का विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया। सप्ताह भर के इस कार्यक्रम में केन्या गणराज्य की माननीय अटॉर्नी जनरल सुश्री डोरकास अगिक अबुया ओडूर के नेतृत्व में 29 वरिष्ठ सिविल सेवकों के साथ-साथ सार्वजनिक सेवा, आंतरिक सुरक्षा, राष्ट्रीय प्रशासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और आर्थिक नियोजन सहित प्रमुख मंत्रालयों/राज्य विभागों के 28 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया (अनुलग्नक-III)।

बहु-देशीय कार्यक्रम:

एनसीजीजी ने 2024-25 में पहली बार अफ्रीकी देशों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एएलडीपी) के अलावा आसियान/आईओआरए देशों, एफआईपीआईसी/आईओआरए देशों, एलएसी देशों और बिम्सटेक देशों के लिए अपने बहु-देशीय क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए (अनुलग्नक-IV)।

अफ़्रीकी राष्ट्र/क्षेत्र के देश:

वर्ष 2024-25 के दौरान, अफ्रीकी क्षेत्र के अनेक देशों के 40 मध्य-स्तरीय सिविल सेवकों के लिए 6 से 17 जनवरी, 2025 के बीच दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। एनसीजीजी ने मार्च 2025 तक अफ्रीकी क्षेत्र के अनेक देशों के 93 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है, जिनमें इरीट्रिया, इथियोपिया, तंजानिया, ट्यूनीशिया, गाम्बिया, सेशेल्स, घाना, केन्या, नामीबिया, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, किंगडम ऑफ एस्वातिनी, युगांडा, कांगो, सिएरा लियोन और मलावी शामिल हैं।

आसियान और आईओआर देश:

एनसीजीजी ने अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासन पर अपना पहला क्षमता विकास कार्यक्रम संचालित किया। 18 से 29 नवंबर, 2024 के बीच आयोजित दो सप्ताह के क्षमता विकास कार्यक्रम में ओमान, श्रीलंका, तंजानिया, केन्या, सेशेल्स, कंबोडिया, मालदीव, मलेशिया और म्यांमार के 30 वरिष्ठ सिविल सेवक शामिल हुए। इसके अलावा वर्ष 2024-25 के दौरान, एनसीजीजी ने आसियान और आईओआर क्षेत्र के अनेक देशों के सिविल सेवकों के लिए दो सप्ताह के दो और कार्यक्रम आयोजित किए। एनसीजीजी ने मार्च 2025 तक आसियान और आईओआर देशों के 80 सिविल सेवकों को प्रशिक्षित किया है।

एफआईपीआईसी/आईओआरए देश:

एनसीजीजी ने 5 से 16 अगस्त, 2024 के बीच एफआईपीआईसी/आईओआरए क्षेत्र के अनेक देशों के 40 सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर अपना पहला उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एएलडीपी) आयोजित किया। इसमें 11 देशों अर्थात सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, सेशेल्स, श्रीलंका, तंजानिया, मेडागास्कर, फिजी, केन्या, मालदीव और मोजाम्बिक के 40 सिविल सेवकों ने भाग लिया।

लैटिन अमरीका और कैरेबियाई (एलएसी) देश:

एनसीजीजी ने 2 से 13 सितंबर 2024 तक लैटिन अमरीका और कैरेबियाई देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर अपना पहला उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया।

दो सप्ताह के एएलडीपी कार्यक्रम में 10 अलग-अलग देशों के 22 वरिष्ठ सिविल सेवकों ने भाग लिया, जिनमें अर्जेंटीना, कोस्टा रिका, अल साल्वाडोर, गुयाना, होंडुरास, जमैका, पराग्वे, पेरू, सेंट किट्स और नेविस और सूरीनाम शामिल थे।

बिम्सटेक देश:

वर्ष 2024-25 के दौरान, बिम्सटेक देशों के 36 सिविल सेवकों के लिए दो सप्ताह का पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम 14 से 25 अक्टूबर, 2024 के बीच आयोजित किया गया। 36 सिविल सेवकों में म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के प्रतिभागी शामिल थे।

II. जिला / शैक्षणिक जुड़ाव तथा अध्ययन दौरे और ताजमहल का दौरा

एनसीजीजी के क्षमता विकास कार्यक्रमों के प्रतिभागियों को क्षेत्रीय भ्रमण के लिए ले जाया जाता है जो उनके क्लासरूम प्रशिक्षण का पूरक होता है। ये दौरे भारत के इतिहास, संस्कृति और हाल की तकनीकी और अवसंरचनात्मक प्रगति आदि की व्यापक समझ प्रदान करते हैं। क्षेत्र दौरों में शामिल हैं:

जिला / शैक्षणिक दौरा: प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को जिला जुड़ाव से अवगत कराया जाता है। वे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, पंजाब और चंडीगढ़ जैसे निकटवर्ती राज्यों के जिला प्रशासन के साथ बातचीत करते हैं। इससे राष्ट्र के जिला और उपमंडल स्तर के प्रशासन के बारे में जानना संभव हो पाता है। मारुति सुजुकी लिमिटेड, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आदि जैसे औद्योगिक संस्थानों के अलावा, शैक्षिक दौरों में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी (आईजीएनएफए) आदि जैसे केन्द्रीय संस्थानों का दौरा भी शामिल है।

अध्ययन दौरे: प्रमुख सरकारी संस्थाओं या राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर अध्ययन दौरे आयोजित किए जाते हैं, जैसे:

नया संसद भवन और संविधान सभा	भारत निर्वाचन आयोग
प्रधानमंत्री संग्रहालय	संघ लोक सेवा आयोग
केंद्रीय जांच ब्यूरो	मुख्य सतर्कता आयोग
शून्य ऊर्जा भवन, पर्यावरण भवन	केंद्रीय सूचना आयोग
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन	नई दिल्ली नगर निगम

ताजमहल का दौरा: अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम आमतौर पर आगरा में ताजमहलमहल और आसपास के ऐतिहासिक महत्व के अन्य स्थानों/विरासत स्थलों के भ्रमण के साथ संपन्न होता है।

III. क्षमता विकास कार्यक्रमों और जिला जुड़ाव में एनसीजीजी द्वारा शुरू किए गए नवाचार

वर्ष 2024-25 के दौरान, एनसीजीजी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू क्षमता विकास कार्यक्रमों (सीबीपी) को मजबूत और प्रासंगिक बनाने के लिए कई सुधार और नवाचार किए। इन प्रयासों में नए संकल्पनात्मक सत्र और विषय आधारित मॉड्यूल शुरू करना शामिल था, जिससे कार्यक्रम की गुणवत्ता में वृद्धि हुई, संकल्पनात्मक स्पष्टता मजबूत हुई, तथा प्रासंगिकता और वैश्विक पहुंच में सुधार हुआ। सामूहिक रूप से, इन पहलों ने अधिकारियों को उत्तरोत्तर डिजिटल और डेटा संचालित परिदृश्य में शासन की मांगों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए तैयार किया है।

एनसीजीजी ने अनुकूलित और समकालीन कार्यक्रम डिजाइन दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू अधिकारियों के लिए देश विशिष्ट आवश्यकताओं, प्रतिभागियों की प्रोफाइल और शासन के उभरते विषयों के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल तैयार किया जाता है। इसमें लक्षित अध्ययन दौरे और व्यावहारिक शिक्षण घटक शामिल थे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और शासन में इसके अनुप्रयोगों पर नए मॉड्यूल ने व्यावहारिक उपयोग के मामलों जैसे कि पूर्वानुमानिक विश्लेषण, सेवा वितरण अनुकूलन और शिकायत निवारण प्रणालियों पर प्रकाश डालने के साथ ही अवसरों, सीमाओं, नैतिक पहलुओं, एल्गोरिदम संबंधी पूर्वाग्रह और मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया। सरकारी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण एक अन्य विषय के रूप में उभरा, जिसमें ई-गवर्नेंस आर्किटेक्चर, इंटरऑपरेबल प्लेटफॉर्म, साइबर सुरक्षा, नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं और प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए संस्थागत क्षमता विकास जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए गए।

समकालीन नीति निर्माण के बारे में प्रतिभागियों की समझ को गहरा करने के लिए, डिजिटल भुगतान जैसे विषयों पर भी सत्र शुरू किए गए: भारतीय कहानी: शासन, बिग डेटा एनालिटिक्स, डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना, शहरी गतिशीलता, लू (हीट वेव्स), ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि सुधार, खाद्य सुरक्षा, ओएनडीसी और एमएसएमई विकास में एआई।

उच्च गुणवत्ता वाले वितरण का समर्थन करने के लिए, एनसीजीजी ने अपने संकाय पूल का विस्तार किया, जिसमें वरिष्ठ सिविल सेवक, डोमेन विशेषज्ञ, युवा व्यवसायी और आईआईटी/आईआईएम के शिक्षाविद शामिल हैं।

मंत्रियों और वरिष्ठ सरकारी लीडर्स के साथ बातचीत से कार्यक्रमों में रणनीतिक और नीति स्तरीय परिप्रेक्ष्य जुड़ गए। वर्ष 202-25 के दौरान अनेक विशेष विषयगत प्रशिक्षण शुरू किए गए। एनसीजीजी ने आईटीईसी के अंतर्गत केन्या के वरिष्ठ सिविल सेवकों के लिए "21वीं सदी में नेतृत्व" जैसे कार्यक्रम शुरू किए। एनसीजीजी द्वारा भागीदार देशों की यात्रा किए जाने के बाद, क्षमता विकास कार्यक्रमों को पुनः डिजाइन किया गया तथा उन्हें इन देशों की अपेक्षाओं और प्रशासनिक संदर्भों के अनुरूप बनाया गया। इसके साथ ही, आईआईटी और आईआईएम के साथ सहयोग से भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के भारतीय सिविल सेवकों को डिजिटल गवर्नेंस, डेटा संचालित गवर्नेंस, एआई और बिग डेटा, ओएनडीसी, ई-कोर्ट और डेटा एनालिटिक्स जैसे उभरते विषयों पर प्रशिक्षण में सुगमता प्रदान की। एनसीजीजी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों द्वारा केस स्टडी की संरचित प्रस्तुतियाँ शुरू करके अपने ज्ञान पारिस्थितिकी तंत्र को भी मजबूत किया, जिन्हें भविष्य में संदर्भ के लिए संग्रहीत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों ने अपने-अपने देशों के लिए नीति और प्रशासनिक समाधानों को पुनः डिजाइन करने, सतत् सहभागिता चैनल का निर्माण करने और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ नेटवर्क को मजबूत करने के लिए संदर्भ बिंदु के रूप में भारत के शासन मॉडल का उपयोग किया।

कार्यक्रम को प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समूह की द्विपक्षीय आवश्यकताओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने के लिए, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (एनयूईपीए) और अनुभूति केंद्र (पीएम गतिशक्ति और ओएनडीसी के लिए) सहित नए संस्थानों को अध्ययन/अध्ययन दौरों में जोड़ा गया।

इस वर्ष अधिक अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी और पूर्व छात्रों का मजबूत नेटवर्क भी देखा गया, जिसमें विशेष रूप से भारत की 'ग्लोबल साउथ' और 'नेबरहुड फर्स्ट' नीति के तहत भागीदार देशों से भागीदारी बढ़ी। एनसीजीजी के प्रशिक्षण कार्यक्रमों में मेडागास्कर, केन्या और इथियोपिया जैसे नए देश शामिल हुए। इसके अतिरिक्त, साझेदार सरकारों के साथ समझौता ज्ञापनों पर सक्रियता से काम किया गया तथा उन पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें मॉरीशस और मेडागास्कर के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन भी शामिल हैं।

इन नवाचारों ने सामूहिक रूप से एनसीजीजी के क्षमता विकास कार्यक्रमों की गुणवत्ता, प्रासंगिकता और रणनीतिक मूल्य को बढ़ाया। उन्होंने एनसीजीजी के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फुटप्रिंट का काफी विस्तार किया और इसके प्रशिक्षण संबंधी हस्तक्षेपों को शासन की उभरती प्राथमिकताओं, डिजिटल परिवर्तन और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ संरेखित किया।

IV. घरेलू *क्षमता विकास* कार्यक्रम

एनसीजीजी ने आईआईएम विशाखापत्तनम के सहयोग से आईआईएम विशाखापत्तनम में "डिजिटल गवर्नेंस" पर अपने प्रथम पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस घरेलू प्रशिक्षण में 11 राज्यों से सूचना प्रौद्योगिकी के 19 वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि

डिजिटल गवर्नेंस किस प्रकार शासन को बेहतर बना सकता है और सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक कुशल बना सकता है (अनुलग्नक **V**)।

V. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलईएडीएस)

अमृत काल के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 2047 में भारत के विजन के अनुरूप, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलईएडीएस) का आयोजन कर रहे हैं। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) के बीच एक सहयोगात्मक पहल है, जो जुलाई 2023 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जटिल परिदृश्य को समझने के लिए करियर-मध्य वैज्ञानिकों को आवश्यक नेतृत्व कौशल और अंतर्दृष्टि से लैस करना है। यह एक सप्ताह का पूर्णतः आवासीय कार्यक्रम है, जो विभिन्न सरकारी प्रयोगशालाओं और शैक्षणिक संस्थानों के वैज्ञानिकों को एक साथ लाता है। इसने प्रशासन, नीति निर्माण और रणनीतिक निर्णय लेने जैसे विषयों पर कार्यशालाएं, सेमिनार और विशेषज्ञों के साथ बातचीत की पेशकश की। एलईएडीएस कार्यक्रम की सफलता भविष्य के वैज्ञानिक प्रशासकों को विकसित करने और अंतःविषय सहयोग को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका को उजागर करती है, जिससे यह भारत के वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण परिसंपत्ति बन गया है।

एनसीजीजी-आईएनएसए के 'विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में नेतृत्व कार्यक्रम (एलईएडीएस)' का पहला बैच वर्ष 2023-24 के दौरान आयोजित किया गया। कार्यक्रम का दूसरा और तीसरा बैच 1 से 7 अप्रैल, 2024 और 8 से 14 जुलाई, 2024 तक क्रमशः 44 और 36 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया गया। प्रतिभागियों में आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, आईआईएसईआर, एनआईपीईआर, डीएसटी, सीएसआईआर, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीआरडीओ, इसरो जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के वैज्ञानिक शामिल थे।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वैज्ञानिक संस्थानों और प्रयोगशालाओं में नेतृत्व और सुशासन के लिए प्रतिभागी वैज्ञानिकों की क्षमता का निर्माण करना है, तथा उन्हें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए इन संस्थानों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए नवीनतम ज्ञान और कौशल से लैस करना है। अब तक, आईएनएसए और एनसीजीजी ने संयुक्त रूप से देश भर के वैज्ञानिक संस्थानों के 125 वैज्ञानिकों के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलईएडीएस) के तीन बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है (अनुलग्नक-VI)।

VI. इंटर्नशिप कार्यक्रम

एनसीजीजी का इंटर्नशिप कार्यक्रम एक अल्पकालिक पहल है जिसे महत्वाकांक्षी नीति निर्माताओं को सार्वजनिक नीति और शासन में अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इंटर्नशिप कार्यक्रम का उद्देश्य राष्ट्रीय भंडार विकसित करने के लिए युवा और स्नातकोत्तर छात्रों को अनुसंधान, आलोचनात्मक अध्ययन, सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण और प्रसार करने का अवसर प्रदान करना है। राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) ने मार्च, 2024 तक इंटर्नशिप कार्यक्रम के 2 बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया है।

2 अप्रैल से 30 जुलाई, 2024 तक एनसीजीजी इंटर्नशिप कार्यक्रम का तीसरा बैच संचालित किया गया, जिसके लिए देश भर से 3,550 से ज़्यादा आवेदन आए। सात दौर के साक्षात्कारों वाली कठोर चयन प्रक्रिया के बाद, 17 प्रशिक्षुओं को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों और अपने-अपने विषय-क्षेत्र के प्रति समर्पण के आधार पर चुना गया। ये प्रशिक्षु आईआईएम शिलांग, आईआईटी कानपुर, दिल्ली विश्वविद्यालय और टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान जैसे कुछ प्रतिष्ठित संस्थानों का प्रतिनिधित्व करते थे। इन प्रशिक्षुओं ने आईआईपीए, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के वरिष्ठ प्रोफेसरों के साथ काम किया, जिन्होंने उनके शोध कार्य का मार्गदर्शन किया। तीसरे बैच के शोध पत्र सुशासन के क्षेत्रों जैसे वित्तीय साक्षरता पहल, इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग का पूर्वानुमान, भारत में डिजिटल मुद्रा परिवर्तन, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार, तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल में ई-गवर्नेंस, आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाई के तहत स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विश्लेषण आदि पर केंद्रित

थे। इन शोध पत्रों को एक व्यापक संग्रह में संकलित किया गया है, जो एनसीजीजी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

20 जनवरी, 2025 से शुरू हुए इंटर्नशिप कार्यक्रम के चौथे बैच के लिए देश भर से 1438 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए और 12 प्रशिक्षुओं का चयन उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के आधार पर किया गया। यह इंटर्नशिप कार्यक्रम बर्मिंघम विश्वविद्यालय, नॉटिंघम विश्वविद्यालय, आईआईटी कानपुर, आईआईटी गुवाहाटी, टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, जामिया हमदर्द विश्वविद्यालय, मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, पांडिचेरी विश्वविद्यालय जैसे प्रमुख संस्थानों से चयनित प्रशिक्षुओं के साथ प्रगति पर है। यह पहल युवा प्रतिभाओं को पोषित करने तथा बेहतर शासन ढांचे के लिए सार्वजनिक नीति अनुसंधान को आगे बढ़ाने के प्रति भारत सरकार की प्रतिबद्धता को उजागर करती है। यह गहन शोध के माध्यम से शासन और नीति से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों का समाधान करने के लिए प्रशिक्षुओं को सशक्त बनाने का एक उपकरण है (अनुलग्नक-VII)।

वेबिनार श्रृंखला

(i) राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार (एनजीजीडब्ल्यू) श्रृंखला

एनसीजीजी ने राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला का आयोजन जारी रखा, जिसमें प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेता/चयनित पहलों को प्रदर्शित किया जाता है। 2022 में नौ वेबिनार आयोजित किए गए, जबकि वर्ष 2023 में दस वेबिनार आयोजित किए गए और वर्ष 2024 के दौरान छह वेबिनार आयोजित किए गए। इन वेबिनारों में 21,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें शासन की नवीन प्रथाओं पर प्रकाश डाला गया और विभिन्न हितधारकों के बीच ज्ञान साझा करने के लिए मंच प्रदान किया गया। इन वेबिनारों में सुशासन पहल के तहत विभिन्न विषयों पर प्रकाश डाला गया, जिन्हें या तो लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से

सम्मानित किया गया था या लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार की विशेषज्ञ समिति के स्तर तक सूचीबद्ध किया गया था। एनजीजीडब्ल्यू श्रृंखला में स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, सामाजिक सेवा जैसे विविध क्षेत्रों को शामिल किया गया तथा राज्यों की असाधारण उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य सर्वोत्तम प्रथाओं और पुरस्कार विजेता उदाहरणों को साझा करना, सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुकरण को प्रेरित करना और नवाचार को बढ़ावा देना था।

वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री पुरस्कार की चयनित पहलों पर डीएआरपीजी के सहयोग से आयोजित पांच राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार की सूची अनुलग्नक-VIII में दी गई है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

1. 26 जुलाई, 2024 को "नवाचार: राज्य श्रेणी" के तहत पीएम पुरस्कार की चयनित पहल पर राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला (एनजीजीडब्ल्यूएस) में 21वां वेबिनार आयोजित किया गया। वैज्ञानिक मृदा, जल संरक्षण और टिकाऊ खेती के लिए भूमि संसाधन सूची (एलआरआई) पर चयनित पहल को कर्नाटक के देवनागेरे जिले के उपायुक्त और जिला मजिस्ट्रेट डॉ. एम.वी. वेंकटेश द्वारा प्रस्तुत किया गया। एलआरआई पहल फसल की उपयुक्तता, पोषक तत्व प्रबंधन, स्थान-विशिष्ट मृदा और जल संरक्षण के उपायों को समझने में सहायता करती है तथा कुशल जल बजट के लिए जल विज्ञान संबंधी मापदंडों को एकीकृत करती है, जिससे परिशुद्ध खेती को बढ़ावा मिलता है। श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, एडिशनल सीईओ, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार ने दूसरी चयनित पहल यानी जीविका (दीदी की रसोई) को प्रस्तुत किया। यह पहल सार्वजनिक अस्पतालों में भर्ती मरीजों और सार्वजनिक आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए गुणवत्तापूर्ण और स्वच्छ भोजन सुनिश्चित करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता पर ध्यान देती है।

2. 30 अगस्त, 2024 को "आकांक्षी जिला कार्यक्रम" के अंतर्गत प्रधानमंत्री पुरस्कार की चयनित पहलों पर राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला में 22वां वेबिनार आयोजित किया गया। इस वेबिनार में प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चयनित दो पहलों को प्रदर्शित किया गया, जिनमें से पहली पहल हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले से संबंधित थी जो हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के निदेशक श्री डी.सी. राणा द्वारा प्रस्तुत की गई। दूसरी चयनित पहल श्रीमती कृष्णा बरुआ, उपायुक्त, बक्सा, असम द्वारा प्रस्तुत की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करके समग्र विकास दृष्टिकोण का उल्लेख किया गया।

3. 27 सितंबर 2025 को "नवाचार: जिला श्रेणी" के तहत प्रधानमंत्री पुरस्कार की चयनित पहलों पर 23वां वेबिनार आयोजित किया गया। पहली पहल तमिलनाडु के रामनाथपुरम में 'प्लास्टिक चेक पोस्ट' पर थी और इसे वहां के डीसी श्री सिमरनजीत सिंह कहलों द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस पहल का उद्देश्य मंडपम वन्यजीव रेंज में अद्वितीय समुद्री जैव विविधता की रक्षा करना था और इस क्षेत्र में प्लास्टिक के प्रवेश को नियंत्रित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी पहल 'आजीविका बढ़ाना: जीवन बदलना' पर थी जिसे ओडिशा के मलकानगिरी में लागू किया गया। यह पहल शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के उप सचिव श्री लिंगराज पांडा द्वारा प्रस्तुत की गई। इस पहल का उद्देश्य मलकानगिरी क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधनों, विशेष रूप से इसके विशाल जलाशयों का लाभ उठाकर मत्स्य पालन को लोगों के लिए आजीविका के वैकल्पिक साधन के रूप में बढ़ावा देना था, जिससे अवैध गतिविधियों और विद्रोही समूहों पर उनकी निर्भरता कम हो सके।

4. 25 अक्टूबर, 2024 को "नवाचार (सामान्य) जिला" के अंतर्गत प्रधानमंत्री पुरस्कार की चयनित पहलों पर राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला में 24वां वेबिनार आयोजित किया गया। श्रीमती हर्षिका सिंह द्वारा प्रस्तुत पहली पहल 'निरक्षरता से आजादी अभियान' पर थी, जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में शुरू की गई पहल थी, जिसका उद्देश्य आदिवासी जिले में कार्यसाधक साक्षरता से निपटना था। 'दस्तावेज डिजिटलीकरण के लिए अक्षय बिग अभियान' (एबीसीडी) पर दूसरी पहल वायनाड के सहायक कलेक्टर श्री एस गौतम राज द्वारा प्रस्तुत की गई। इस पहल का उद्देश्य वायनाड में जनजातीय समुदायों को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराना था।

5. 29 नवंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक प्रो. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन की पुस्तक "इंडिया@100 - प्रशासनिक सुधार" पर 25वां वेबिनार आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक प्रो. कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यन ने भारत के विकास को गति देने के लिए शासन को बेहतर बनाने, आर्थिक दक्षता को बढ़ावा देने और नौकरशाही की संरचनाओं में सुधार पर व्याख्यान दिया।

(ii) एनसीजीजी *की* सुशासन: नीतियां और अभ्यास वेबिनार श्रृंखला

एनसीजीजी ने आईआईटी और आईआईएम के सहयोग से सुशासन वेबिनार श्रृंखला का आयोजन शुरू किया है, जिनके साथ एनसीजीजी द्वारा समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 2024-25 के दौरान एनसीजीजी ने आईआईएम लखनऊ के साथ 29 सितंबर, 2024 को; आईआईटी कानपुर के साथ 24 अक्टूबर, 2024 को; आईआईएम सिरमौर के साथ 21 नवंबर, 2024 को; मिज़ोरम सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ 13दिसंबर, 2024 को; आईआईएम तिरुचिरापल्ली के साथ 24 जनवरी, 2025 को; आईआईएम काशीपुर के साथ 25 फरवरी, 2025 को और आईआईटी जोधपुर के साथ 27 मार्च, 2025 को सात सुशासन: नीतियां और अभ्यास वेबिनार आयोजित किए हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान आईआईटी/आईआईएम के सहयोग से आयोजित सात सुशासन: नीतियां और अभ्यास वेबिनार की सूची अनुलग्नक-IX में दी गई है।

VII. प्रकाशन

एनजीजीडब्ल्यू (राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार) की कार्यवाही रिपोर्ट: एनसीजीजी की वेबसाइट (ncgg.org.in) पर पांच कार्यवाही रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं जिनमें राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार में आयोजित प्रमुख चर्चाओं और प्रस्तुतियों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। ये रिपोर्ट वेबिनार के विषय पर प्रकाश डालती हैं और वेबिनार के दौरान प्रस्तुत सर्वोत्तम प्रथाओं और लोक प्रशासन पर इसके प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं।

इंटर्नशिप कार्यक्रम शोध पत्र – तीसरा बैच: तीसरे बैच के प्रशिक्षुओं द्वारा प्रस्तुत कुल सत्रह शोध पत्रों को एनसीजीजी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। ये शोध पत्र शासन में सुधार के लिए नवीन दृष्टिकोणों पर प्रकाश डालते हैं तथा सार्वजनिक संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता बढ़ाने के लिए नए मॉडलों की खोज करते हैं। वे विविध विषयों पर गहन विश्लेषण को भी दर्शाते हैं, तथा शासन की समकालीन चुनौतियों के लिए नए दृष्टिकोण और व्यावहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। प्रत्येक शोध पत्र नीति निर्माण, कार्यान्वयन और लोक प्रबंधन के विशिष्ट पहलुओं पर गहनता से विचार करता है तथा लोक प्रशासन पर चर्चा में योगदान देता है। शोध के परिणाम विभिन्न स्तरों पर शासन के ढांचे को मजबूत करने के लिए चल रहे प्रयासों के अनुरूप हैं (ncgg.org.in)।

आईएनएसए - एनसीजीजी का 'विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नेतृत्व कार्यक्रम (एलईएडीएस)' - दूसरे और तीसरे बैच की रिपोर्ट: आईएनएसए-एनसीजीजी के एलईएडीएस कार्यक्रम के दूसरे और तीसरे बैच की रिपोर्टों को

एनसीजीजी की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। रिपोर्ट में एलईएडीएस के रोडमैप, कार्यक्रम अनुसूची और सत्र विवरण तथा एलईएडीएस कार्यक्रम की आगे की रणनीति पर प्रकाश डाला गया है (ncgg.org.in)।

VIII. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: एनसीजीजी ने विकासशील देशों के साथ सहयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को आगे बढ़ाना जारी रखा है। ये सहयोग सार्वजनिक नीति और शासन में ज्ञान और सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सरकारी निकायों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान सात समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिनका विवरण अनुलग्नक-X में दिया गया है और संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है:

i) मालदीव के सिविल सेवकों के प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम , पर एनसीजीजी और मालदीव सिविल सेवा आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मालदीव के 1000 सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए 9 अगस्त 2024 की प्रभावी तिथि के साथ 5 वर्ष की एक और अवधि के लिए नवीकृत किया गया।

ii) एनसीजीजी और श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान, लोक प्रशासन मंत्रालय, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार, श्रीलंका के बीच श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम पर समझौता ज्ञापन पर 10 दिसंबर, 2024 को हस्ताक्षर किए गए, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए या भारत में श्रीलंका के 1500 सिविल सेवकों को प्रशिक्षण दिए जाने तक प्रभावी रहेगा।

iii) मॉरीशस के लोक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम पर एनसीजीजी और मॉरीशस गणराज्य के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर 11 मार्च 2025 को हस्ताक्षर किए गए, जो 5 वर्ष की अवधि के लिए या भारत में मॉरीशस के 500 लोक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिए जाने तक प्रभावी रहेगा।

iv) 24 से 27 मार्च 2025 तक एनसीजीजी के महानिदेशक के नेतृत्व में एनसीजीजी के प्रतिनिधिमंडल की एंटानानारिवो, मेडागास्कर की यात्रा के दौरान एनसीजीजी और राष्ट्रीय प्रशासन स्कूल, श्रम, रोजगार और सिविल सेवा मंत्रालय, मेडागास्कर सरकार के बीच 25 मार्च, 2025 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

IX. आउटरीच की गतिविधियाँ

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल के दौरे:

बांग्लादेश की यात्रा: 2024 से 2029 की अवधि के लिए एनसीजीजी और लोक प्रशासन मंत्रालय, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण के संबंध में द्विपक्षीय चर्चा के लिए प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) के सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने **28-30 अप्रैल 2024 तक बांग्लादेश** का दौरा करने वाले चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। यह यात्रा बांग्लादेश के लोक प्रशासन मंत्रालय के निमंत्रण पर की गई और इसका ध्यान बांग्लादेश के सिविल सेवकों के लिए प्रशासन के क्षेत्र में करियर-मध्य क्षमता विकास कार्यक्रमों पर केंद्रित था।

श्रीलंका की यात्रा: श्री वी. श्रीनिवास, सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय और एनसीजीजी के महानिदेशक ने 7 से 9 जुलाई 2024 तक श्रीलंका का दौरा करने वाले 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया। इस यात्रा के दौरान सार्थक विचार-विमर्श और रणनीतिक बैठकें हुईं, जिससे 10 दिसंबर, 2024 को श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान (एसएलआईडीए) और एनसीजीजी के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। 7-9 जुलाई, 2024 तक कोलंबो की

2 दिवसीय यात्रा में 9 जुलाई, 2024 को संसद परिसर में तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री महामहिम श्री दिनेश चंद्र रूपसिंघे गुणवर्धने से शिष्टाचार भेंट शामिल थी।

मॉरीशस के प्रतिनिधिमंडल का दौरा: मॉरीशस के तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मॉरीशस के सार्वजनिक अधिकारियों के लिए एनसीजीजी द्वारा क्षमता विकास कार्यक्रम आयोजित करने तथा मॉरीशस के सार्वजनिक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम पर एनसीजीजी और मॉरीशस गणराज्य के लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से सहयोग के संबंध में 23 से 26 सितंबर, 2024 तक दिल्ली का दौरा किया।

श्रीलंका की यात्रा: एनसीजीजी के महानिदेशक डॉ. सुरेन्द्र कुमार बागड़े ने श्रीलंका सरकार के लोक प्रशासन, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार मंत्रालय के निमंत्रण पर समझौता ज्ञापन के प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन के तौर-तरीकों को पुख्ता करने के लिए 17-20 फरवरी 2025 तक श्रीलंका का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। एनसीजीजी के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. आशुतोष पाल सिंह भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

प्रतिनिधिमंडल ने श्रीलंका के माननीय प्रधानमंत्री डॉ. हरिनी अमरसूर्या और माननीय लोक प्रशासन, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार मंत्री डॉ. ए.एच.एम.एच. अबयारत्ना से मुलाकात की और श्रीलंका के राष्ट्रपति के सचिव डॉ. एन.एस. कुमानायके, श्रीलंका के प्रधानमंत्री के सचिव श्री जी.पी. सपुथंथरी और लोक प्रशासन, प्रांतीय परिषद और स्थानीय सरकार मंत्रालय के सचिव श्री एस. आलोक बंडारा के साथ भी बैठकें कीं।

प्रतिनिधिमंडल ने कैंडी जिला सचिवालय का भी दौरा किया तथा मध्य और उत्तर पश्चिमी प्रांतों में तैनात एनसीजीजी के पूर्व छात्रों से बातचीत की।

मेडागास्कर की यात्रा: राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी) के महानिदेशक डॉ. सुरेन्द्र कुमार बागड़े ने 25 मार्च, 2025 को राष्ट्रीय सुशासन केंद्र (एनसीजीजी), प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार और राष्ट्रीय प्रशासन स्कूल, श्रम, रोजगार और सिविल सेवा मंत्रालय, मेडागास्कर सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने के लिए 24 से 27 मार्च 2025 तक मेडागास्कर का दौरा करने वाले प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।

X. प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी

अपने अधिदेश के अंग के रूप में, एनसीजीजी अपने अनुसंधान और घरेलू क्षमता विकास पहलों को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख संस्थानों के साथ अपनी पहुंच का विस्तार और साझेदारी करना जारी रखे हुए है। वर्ष 2024-25 के दौरान, एनसीजीजी ने 4 आईआईटी अर्थात आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी कानपुर और आईआईटी जोधपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान 5 आईआईएम अर्थात आईआईएम कलकत्ता, आईआईएम लखनऊ, आईआईएम तिरुचिरापल्ली, आईआईएम काशीपुर और आईआईएम सिरमौर के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान मिजोरम विश्वविद्यालय और सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान, गुजरात के साथ भी समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नई साझेदारियां अनुसंधान की क्षमताओं को मजबूत करेंगी और क्षमता विकास के बहुआयामी दृष्टिकोण के माध्यम से एनसीजीजी के प्रभाव को व्यापक बनाएंगी (अनुलग्नक-XI)।

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की परिकल्पना संस्थानों और हितधारकों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के रूप में की गई है जो अनुसंधान, ज्ञान साझाकरण, सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुरूप शासन संबंधी सुधारों के कार्यान्वयन के लिए समर्पित है। इन साझेदारियों के माध्यम से एनसीजीजी राष्ट्रीय सुशासन ग्रिड (एनजीजीजी) की स्थापना का नेतृत्व कर रहा है।

XII. वित्त

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) और वित्त मंत्रालय ने एनसीजीजी को विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए मजबूत समर्थन प्रदर्शित किया है। अपनी गतिविधियों के निष्पादन को सुगम बनाने के लिए, सरकार ने एनसीजीजी के लिए अनुदान सहायता को 2024-25 में 14.07 करोड़ रुपये के निर्धारित बजट

अनुमान से बढ़ाकर 19.00 करोड़ रुपये कर दिया है। एनसीजीजी के लिए अनुदान सहायता के अंतर्गत बजट को 2025-26 में बढ़ाकर 21.50 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

अनुलग्नक-I

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र का शासी निकाय

1	कैबिनेट सचिव	अध्यक्ष
2	सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	उपाध्यक्ष
3	सचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
4	सचिव, ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5	सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
6	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
7	सचिव, उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
8	सचिव, आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
9	सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
10	सचिव, कृषि, सहकारिता एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
11	शिक्षाविद/प्रख्यात प्रशासक/विशेषज्ञ/प्रख्यात नवप्रवर्तक/प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रमुख	सदस्य (5)
12	महानिदेशक, एनसीजीजी	सदस्य - सचिव

अनुलग्नक-II

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र की प्रबंधन समिति

1	सचिव, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव समन्वय, कैबिनेट सचिवालय	सदस्य
3	कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग	सदस्य
4	ग्रामीण विकास विभाग	सदस्य
5	आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	सदस्य
6	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
7	उच्च शिक्षा विभाग	सदस्य
8	आर्थिक कार्य विभाग	सदस्य
9	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	सदस्य
10	कृषि, सहकारिता एवं परिवार कल्याण विभाग	सदस्य
11	विशेष सचिव एवं वित्त सलाहकार (गृह मंत्रालय)	सदस्य
12	महानिदेशक, एनसीजीजी	सदस्य - सचिव

अनुलग्नक-III

2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम - एकल देशीय

क्र. सं.	बैच	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
बांग्लादेश			
1	72वीं सीबीपी	15 -26 जुलाई, 2024	45
2	विशेष सीबीपी	15 - 20 जुलाई, 2024	16
मालदीव			
1	33वीं सीबीपी	09-20 सितंबर, 2024	34
2	34वीं सीबीपी	14 - 25 अक्टूबर, 2024	35
3	35वीं सीबीपी	09-18 जनवरी, 2025	35
श्रीलंका			
1	तीसरी सीबीपी	13-24 मई, 2024	41
2	चौथी सीबीपी	22 - 02 अगस्त, 2024	40
3	पांचवीं सीबीपी	19-30 अगस्त, 2024	39
4	छठी सीबीपी	09-20 दिसंबर, 2024	40
5	सातवीं सीबीपी	17-28 मार्च, 2025	40
कंबोडिया			
1	पांचवीं सीबीपी	24 जून - 05 जुलाई, 2024	40
2	छठी सीबीपी	23 सितंबर - 04 अक्टूबर, 2024	39
3	सातवीं सीबीपी	25 नवंबर – 06 दिसंबर, 2024	40
4	आठवीं सीबीपी	09-20 दिसंबर, 2024	39
5	नौवीं सीबीपी	10– 21 फरवरी, 2025	39
6	10वीं सीबीपी	10 – 21 मार्च, 2025	40
गाम्बिया			
1	चौथी सीबीपी	27 मई – 07 जून, 2024	30
2	पांचवीं सीबीपी	24 फरवरी – 7 मार्च, 2025	18
तंजानिया			
1	"परियोजना डिजाइन और जोखिम प्रबंधन" पर प्रथम सीबीपी	06-17 मई, 2024	39
कीनिया			
1	'नेतृत्व और राष्ट्रीय परिवर्तन' पर विशेष सीबीपी	13-18 जनवरी, 2025	29

अनुलग्नक-IV

2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय क्षमता विकास कार्यक्रम - बहु-देशीय

क्र. सं.	कार्यक्रम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	एफआईपीआईसी/आईओआरए क्षेत्र के अनेक देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम	5 - 16 अगस्त, 2024	40
2	लैटिन अमेरिकी और कैरेबियाई क्षेत्र के अनेक देशों के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और शासन पर उन्नत नेतृत्व विकास कार्यक्रम	2 – 13 सितंबर, 2024	22
3	बिम्सटेक देशों के लिए पहला करियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	14 - 25 अक्टूबर, 2024	36
4	अफ़्रीकी क्षेत्रों के अनेक देशों के मध्य-स्तरीय सिविल सेवकों के लिए करियर-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	6 - 17 जनवरी, 2025	40
दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के देश			
5	दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए सार्वजनिक नीति और प्रशासन पर प्रथम सीबीपी	18 - 29 नवंबर, 2024	30
6	दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए भूमि और उत्पाद शुल्क प्रबंधन पर द्वितीय सीबीपी	24 फरवरी – 7 मार्च, 2025	28
7	दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र के सिविल सेवकों के लिए स्थानीय शासन पर तृतीय सीबीपी	10 – 21 मार्च, 2025	20

अनुलग्नक-V

2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा संचालित घरेलू क्षमता विकास कार्यक्रम

क्र. सं.	बैच	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	डिजिटल गवर्नेंस पर प्रथम पांच दिवसीय आईआईएमवी - एनसीजीजी प्रशिक्षण कार्यक्रम	29 जुलाई - 02 अगस्त, 2024	19

अनुलग्नक-VI

2024-25 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आयोजित एनसीजीजी - आईएनएसए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलईएडीएस)

क्र. सं.	बैच	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में द्वितीय एनसीजीजी - आईएनएसए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलईएडीएस)	01 - 07 अप्रैल, 2024	44
2	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में तृतीय एनसीजीजी - आईएनएसए नेतृत्व विकास कार्यक्रम (एलईएडीएस)	08 - 14 जुलाई, 2024	37

अनुलग्नक-VII

एनसीजीजी के इंटर्नशिप कार्यक्रम का विवरण

क्र. सं.	बैच	अवधि	इंटर्न की संख्या
1	इंटर्नशिप कार्यक्रम का तीसरा बैच	02 अप्रैल– 30 जुलाई, 2024	17

अनुलग्नक-VIII

2024-25 के दौरान प्रधानमंत्री पुरस्कार लिए चयनित पहलों पर आयोजित राष्ट्रीय सुशासन वेबिनार श्रृंखला

क्र. सं.	वेबिनार	सत्र	तिथि
1	'नवाचार - राज्य श्रेणी' पर 21वां वेबिनार	सत्र 1 : भूमि संसाधन सूची (एलआरआई), कर्नाटक सत्र 2 : जीविका (दीदी की रसोई) पहल, बिहार	26 जुलाई, 2024
2	'आकांक्षी जिला कार्यक्रम' पर 22वां वेबिनार	सत्र 1 : हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहल सत्र 2 : असम के बक्सा जिले में पहल	30 अगस्त, 2024
3	'नवाचार: जिला श्रेणी'पर 23वां वेबिनार	सत्र 1 : प्लास्टिक चेक पोस्ट-मंडपन, वन्यजीव रेंज पहल, रामनाथपुरम सत्र 2 : आजीविका में वृद्धि: जीवन परिवर्तन पहल, मलकानगिरी	27 सितंबर, 2024
4	'नवाचार (सामान्य) जिला' पर 24वां वेबिनार	सत्र 1 : निरक्षरता से आजादी अभियान, मंडला, मध्य प्रदेश सत्र 2 : दस्तावेज डिजिटलीकरण के लिए अक्षय बिग अभियान, वायनाड, केरल	25 अक्टूबर, 2024
5	'इंडिया@100 - प्रशासनिक सुधार' पर 25वां वेबिनार	इंडिया@100 – प्रशासनिक सुधार	29 नवंबर, 2024

अनुलग्नक-IX

2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा आयोजित सुशासन: नीतियां और अभ्यास वेबिनार श्रृंखला

क्र. सं.	वेबिनार	सत्र	तिथि
1	**आईआईएम लखनऊ** के सहयोग से पहला वेबिनार	सत्र 1 : स्वास्थ्य संबंधी विश्वास शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा संबंधों को कैसे आकार देते हैं - प्रो. क्षितिज अवस्थी सत्र 2 : डेटा गवर्नेंस - प्रो. वी एस प्रकाश अत्तिली	20 सितंबर, 2024
2	आईआईटी कानपुर के सहयोग से द्वितीय वेबिनार	सत्र 1 : भारत में सार्वजनिक नीति का उभरता परिदृश्य - डॉ. अजय कुमार सत्र 2 : डिजिटल अर्थव्यवस्था में प्लेटफ़ॉर्म बिज़नेस मॉडल और उनका विनियमन - प्रो. विमल कुमार	24 अक्टूबर, 2024
3	**आईआईएम सिरमौर** के सहयोग से तीसरा वेबिनार	सत्र 1 : आतंकवादी समूह और सरकार की नीति की तर्कसंगतता: एक खेल सैद्धांतिक दृष्टिकोण - प्रोफ़ेसर ऐश्वर्या हरिचंदन सत्र 2 : इन्फ्रास्ट्रक्चर मेगा-प्रोजेक्ट्स में पब्लिक इश्यू मैनेजमेंट : बैंगलोर हवाई अड्डे का मामला - डॉ. कल्पना गोपालन	21 नवंबर, 2024
4	**मिजोरम केंद्रीय विश्वविद्यालय** के सहयोग से चौथा वेबिनार	सत्र 1 : सुशासन के सिद्धांत और व्यवहार: भारत के उत्तर पूर्व से उदाहरण - प्रो. श्रीनिबास पाथी सत्र 2 : भारत में सुशासन पहल: विकास की आधारशिला - डॉ. टी. सदाशिवम	13 दिसंबर, 2024
5	**आईआईएम तिरुचिरापल्ली** के सहयोग से 5वां वेबिनार	सत्र 1 : भारत ने रिवर्स माइग्रेशन के माध्यम से कोविड-19 के झटकों का सामना किया - प्रो. सौमेन मजूमदार सत्र 2 : प्रवासियों को सहायता देने के लिए शहरी शासन नीतियाँ - श्री शैलेश के. पाठक	24 जनवरी, 2025
6	**आईआईएम काशीपुर** के सहयोग से छठा वेबिनार	सत्र 1 : जलवायु परिवर्तन, वर्षा में विविधता और खाद्य उत्पादन की चुनौतियाँ - डॉ. अतुलन गुहा सत्र 2 : शासन में डिजिटल परिवर्तन - डॉ. हरीश कुमार	25 फरवरी, 2025
7	**आईआईएम जोधपुर** के सहयोग से सातवां वेबिनार	सत्र 1 : 'रणनीतिक दूरदर्शिता और नीति' - डॉ. कृष्ण कुमार बलरामन सत्र 2 : 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) शिक्षा और नीति'- डॉ. वेंकट राम रेड्डी गनुथुला	27 मार्च, 2025

अनुलग्नक-X

2024-25 के दौरान एनसीजीजी द्वारा हस्ताक्षरित अंतर्राष्ट्रीय समझौता ज्ञापन

क्र. सं.	समझौता ज्ञापन	समझौता ज्ञापन का विषय	वैधता की अवधि और वर्षों की कुल संख्या	समझौता ज्ञापन की अवधि के दौरान प्रशिक्षित किए जाने वाले सिविल सेवकों की संख्या
1	एनसीजीजी और श्रीलंका विकास प्रशासन संस्थान (एसएलआईडीए), लोक प्रशासन, गृह, स्थानीय सरकार और प्रांतीय परिषद मंत्रालय, श्रीलंका	श्रीलंका के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम	10.12.2024 से 09.12.2029 5 वर्ष	1500
2	एनसीजीजी और मालदीव सिविल सेवा आयोग, मालदीव गणराज्य	मालदीव के सिविल सेवकों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम	9.08.2024 से 8.08.2029 5 वर्ष	1000
3	एनसीजीजी और लोक सेवा एवं प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, मॉरीशस गणराज्य	मॉरीशस के लोक अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास कार्यक्रम	11.03.2025 से 10.03.2030 5 वर्ष	500
4	एनसीजीजी और राष्ट्रीय प्रशासन स्कूल, श्रम, रोजगार और सिविल सेवा मंत्रालय, मेडागास्कर सरकार	मेडागास्कर के सिविल सेवकों के लिए क्षमता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम	25.03.2025 से 24.03.2028 3 वर्ष	250

अनुलग्नक-XI

2024-25 के दौरान राष्ट्रीय संस्थानों/विभागों/विश्वविद्यालयों के साथ एनसीजीजी द्वारा हस्ताक्षरित घरेलू समझौता ज्ञापन

क्र. सं.	संस्थान / विभाग / विश्वविद्यालय	से	तक वैध	अवधि
1	आईआईटी बॉम्बे	जनवरी, 2025	जनवरी, 2030	5 वर्ष
2	आईआईटी रुड़की	22 जनवरी, 2025	21 जनवरी, 2030	5 वर्ष
3	आईआईटी कानपुर	09 अगस्त, 2024	08 अगस्त, 2029	5 वर्ष
4	आईआईटी जोधपुर	12 अगस्त, 2024	11 सितंबर, 2029	5 वर्ष
5	आईआईएम कलकत्ता	13 दिसंबर, 2024	12 दिसंबर, 2029	5 वर्ष
6	आईआईएम काशीपुर	04 सितंबर, 2024	03 सितंबर, 2029	5 वर्ष
7	आईआईएम लखनऊ	05 अगस्त, 2024	04 अगस्त, 2029	5 वर्ष
8	आईआईएम तिरुचिरापल्ली	27 सितंबर, 2024	26 सितंबर, 2029	5 वर्ष
9	आईआईएम सिरमौर	16 अगस्त, 2024	30 जुलाई, 2029	5 वर्ष
10	मिजोरम विश्वविद्यालय, आइजोल	16 अगस्त, 2024	15 अगस्त, 2029	5 वर्ष
11	सरदार पटेल लोक प्रशासन संस्थान, गुजरात	25 दिसंबर, 2024	24 दिसंबर, 2029	5 वर्ष
12	आईएनएसए	06 मार्च, 2024	05 मार्च, 2029	5 वर्ष

सत्यमेव जयते
Government of India
NCGG
National Centre for Good Governance
The Torch Bearer of Good Governance

राष्ट्रीय सुशासन केंद्र

नौवां तल, एनडीसीसी - 2 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली,
दिल्ली - 110 001 (भारत)
+91-11-2140 1195

NCGG_GoI
www.ncgg.org.in
NCGGIndia